Exchange & Finance Available
Zelo Electric Scooter
Maa Bhagwati Services & Enterprises
B. No. 23, Infront of IDBI Bank,
Neemuch 9407423966, 8770664866

मालवा फर्स्ट

MALWA FIRST

स्वाभिमान ही हमारा अभिमान है

Periodicity- Weekly

PRGI Reg. No. MPHIN/2023/90883

संपादक : ऐश्वर्य शर्मा

नीमच, बुधवार
11 फरवरी 2026

वर्ष - 03, अंक - 41 - मूल्य 02 रूपए
पृष्ठ - 04

E-mail: nmh.pawan@gmail.com
Contact: 9407423966, 8770664866

Commodity: Gold 99,735 Silver 97,000 Crude Oil 5,963 Natural Gas 302.20 Aluminium 232.30 Copper 827.35

बजट प्रस्तावों में सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास तथा कल्याण का रखा गया है ध्यान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों और मछुआरों की आर्थिक समृद्धि के लिए संकल्प के साथ कार्य कर रही है। मध्यप्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है, इसके साथ हमें मत्स्य उत्पादन में भी सक्रियता से कार्य कर आने वाले वर्षों में इसे दोगुना करने की दिशा में काम करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रदेश में मछली पालन के साथ ही एक्वाकल्चर के क्षेत्र में भी कार्य किया जाए। प्रदेश में ऐसा इको सिस्टम तैयार किया जाए, जिससे मछुआरों का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषक कल्याण को समर्पित करते हुए यह वर्ष मना रही है। मध्यप्रदेश को मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। मछुआ सम्मेलन आयोजित कर मत्स्य पालन में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाए। सीड प्रोडक्शन बढ़ाने की दिशा में कार्य करें। प्रदेश में संचालित मत्स्य महासंघ के सुव्यवस्थित उपयोग के लिए भी कार्य करने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि कम भू-जल स्तर वाले जिलों में फॉर्म पॉन्ड मॉडल के माध्यम से मत्स्य उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एक जिले को मॉडल के रूप में तैयार किया जाए, जिसमें मत्स्य उत्पादन के साथ ही सिंघाड़ा, कमल गट्टा, मखाना सहित अन्य एक्वाकल्चर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्रदेश में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मध्यप्रदेश केज कल्चर नीति पर कार्य किया जा रहा है। इसमें 10 हजार केज हितग्राही मूलक योजना में और 90 हजार केज उद्यमी मॉडल के अंतर्गत तैयार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के विषय में भी अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी।

फॉलोअप : मानसिक दबाव और लगातार ड्यूटी ने बढ़ाया तनाव, मृतक की बेटी और पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

खराब पुलिस सिस्टम ने ली हेड कॉन्स्टेबल की जान

बेटी का आरोप- बीमारी और चार ऑपरेशन के बावजूद कराई जा रही थी भारी ड्यूटी

नीमच 9 फरवरी (निप्र)। हेड कॉन्स्टेबल होशियार सिंह की मौत ने पुलिस विभाग के भीतर कार्यप्रणाली और ड्यूटी अलॉटमेंट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी बेटी अर्पिता यादव का कहना है कि लंबे समय से उनके पिता पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था। बीमारी और चार ऑपरेशन के बावजूद उनसे भारी ड्यूटी कराई जा रही थी, जिससे वे लंबे समय से तनाव में थे।

अधिकारी लगातार कर रहे थे परेशान - अर्पिता के अनुसार उनके पिता को RI और अन्य वरिष्ठ अधिकारी लगातार परेशान करते थे। उन्होंने कम ड्यूटी देने की मांग की थी, लेकिन इसके उलट उनकी ड्यूटी और बढ़ा दी जाती थी। यही लगातार दबाव उनके लिए असहनीय साबित हुआ।

छुट्टी बढ़ाने गए थे, घर से सामान्य हाल में निकले थे - अर्पिता ने बताया कि होशियार सिंह की छुट्टी खत्म हो रही थी। छुट्टी बढ़ाने के लिए वे कंट्रोल रूम गए थे। घर से निकलते समय उन्होंने परिवार से सामान्य बातचीत की, खाना खाया और बिल्कुल ठीक हालत में निकले थे। बाद में पता चला कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पहले ही लिखा था जिम्मेदारी विभाग की - परिवार का कहना है कि होशियार सिंह ने विभाग को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि अगर उनके साथ कुछ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी विभाग की होगी। ऑपरेशन के बाद भी उन पर ड्यूटी का दबाव बना रहा।

न एसपी पहुंचे न कोई वरिष्ठ अधिकारी - कमलेश बाई ने कहा कि पति की मौत के बाद न तो एसपी और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की।

जहर खाने की वजह अभी भी अस्पष्ट - कैंट थाना प्रभारी टीआई नीलेश अवस्थी ने कहा कि फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हेड कॉन्स्टेबल ने जहर क्यों खाया। मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है।

पत्नी का आरोप पैसे देने वालों की ड्यूटी नहीं लगती

मृतक की पत्नी कमलेश बाई ने आरोप लगाया कि जो लोग पैसे देते थे, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी। जबकि जो पैसे नहीं देते थे, उनसे सुबह-शाम लगातार ड्यूटी कराई जाती थी। इसी कारण उनके पति लंबे समय से तनाव में थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति के पास से मोबाइल फोन गायब है।

पोस्टमार्टम के बाद भी परिवार को शव के पास नहीं जाने दिया

- पुलिस ने परिवार को शव के साथ जाने से रोका और करीब 7 किलोमीटर दूर उतार दिया। पत्नी के अनुसार, पोस्टमार्टम के दौरान परिवार पुलिस लाइन स्थित घर पर इंतजार कर रहा था, लेकिन उन्हें अलग वाहन में बैठाकर रवाना कर दिया गया।

बोले एसपी : चार विभागीय जांच हो चुकी

एसपी जायसवाल ने कहा कि हेड कांस्टेबल होशियार सिंह के विभागीय रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि उनके खिलाफ चार विभागीय जांच हो चुकी थी, जिसमें उन्हें चार बड़ी सजाएं दी गई थीं। इसके अलावा वह कई बार लंबी अवधि की छुट्टियों पर भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से अशोभनीय व्यवहार करने के आरोप भी उन पर लगे हैं। हालांकि, पिछले डेढ़ महीने की ड्यूटी रजिस्टर जांच में किसी प्रकार की हार्ड ड्यूटी या प्रताड़ना जैसी कोई बात सामने नहीं आई है। आरक्षक की पत्नी कमलेश बाई के आरोप को लेकर एसपी जायसवाल ने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने से लेकर पोस्टमार्टम तक मृतक के परिजन उनके साथ मौजूद थे। मृत्यु के बाद शव गृह में भी परिवार के सदस्य थे। मृतक के भाई एवं परिजनों से उन्होंने खुद मुलाकात की थी। पुलिस प्रशासन परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है।

सीआरपीएफ परिसर में का मामला : अंगूठी और मोबाइल से हुई मृतक की पहचान

झाड़ियों के बीच मिला लापता जवान का कंकाल

मंदसौर रेफर : मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव का विस्तृत पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच अब मंदसौर में होगी

नीमच 9 फरवरी (निप्र)। शहर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल परिसर में रविवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब सफाई कार्य के दौरान झाड़ियों में एक मानव कंकाल मिला। प्रारंभिक जांच और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर इस कंकाल की पहचान करीब सवा महीने से लापता सीआरपीएफ जवान नंदकिशोर प्रजापत के रूप में हुई है। पुलिस ने कपड़ों, मोबाइल फोन और अंगूठी के आधार पर शिनाख्त की पुष्टि की है।

27 दिसंबर से लापता थे जवान - जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान नंदकिशोर (44) पुत्र अमरचंद प्रजापत, निवासी ग्राम भीम, जिला राजसमंद (राजस्थान) के रूप में हुई है। नंदकिशोर नीमच स्थित सीआरपीएफ कैंप में पदस्थ थे और बीते 27 दिसंबर 2025 से रहस्यमयी ढंग से लापता थे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नीमच कैंट थाने में पहले से ही दर्ज थी। रविवार को जब परिसर में सफाई चल रही थी, तब जवानों की नजर इस कंकाल पर पड़ी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी जांच - मामले में पुलिस का कहना है कि मौत प्राकृतिक है, दुर्घटना है या कोई साजिश, इसका खुलासा फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

वैज्ञानिक परीक्षण के लिए मंदसौर भेजा शव

घटना की सूचना मिलते ही सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी और कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कंकाल को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत की गुत्थी सुलझाने और विस्तृत वैज्ञानिक परीक्षण के लिए इसे मंदसौर रेफर कर दिया गया है। जांच के दौरान मृतक के परिजन और चिकित्सकीय टीम भी साथ रही।

सीएम राइज स्कूल में सुरक्षा फेल, छात्र घायल

सीएम राइज स्कूल में लापरवाही का आरोप : रैक गिरने से केजी-2 के छात्र का पैर टूटा, कार्रवाई की मांग

जावद, निप्र। जावद स्थित संदीपनी स्कूल (सीएम राइज) एक बार फिर अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में आ गया है। सोमवार दोपहर रेस्ट के दौरान केजी-2 कक्षा में अध्ययनरत 8 वर्षीय छात्र विनायक, पिता राहुल नायक, निवासी खोर, का पैर टूट गया। जानकारी के अनुसार छात्र कक्षा में सामान रखने की रैक के नीचे खड़ा था, जबकि कुछ अन्य बच्चे ऊपर चढ़कर मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान असंतुलित होकर रैक नीचे गिरी और छात्र के पैर पर आ लगी, जिससे उसे गंभीर चोट आई।

आरोप : दर्द से तड़पता रहा छात्र - घटना के बाद छात्र दर्द से तड़पता रहा, लेकिन आरोप है कि स्कूल स्टाफ द्वारा उसे तत्काल अस्पताल नहीं पहुंचाया गया।

शिक्षक गोपाल चंदेल ने फोन पर छात्र के पिता को सूचना दी। पिता उस समय मंदसौर में थे, जिसके बाद परिजनों को जानकारी दी गई। परिजन जब स्कूल पहुंचे तो छात्र रोता हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि शिक्षक ने उसे टेबल पर बैठा रखा था, जबकि वह लगातार दर्द से कराह रहा था। क्लास में कार्यरत शिक्षिका उस दौरान लंच कर रही थी।

छात्र का उपचार जारी - इसके बाद परिजन छात्र को दोपहिया वाहन से नीमच के एक निजी चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने पैर में फ्रैक्चर बताया। फिलहाल छात्र का उपचार जारी है।

परिजनों ने की कार्रवाई की मांग : परिजनों ने सीएम राइज स्कूल के स्टाफ पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि कोई बड़ी दुर्घटना या जनहानि हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता।

इनका कहना है...

"मैं उस समय दूसरी बिल्डिंग में थी, मुझे तत्काल सूचना नहीं दी गई। जब जानकारी मिली, तब तक परिजन स्कूल पहुंच चुके थे। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जाएगी और उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।"

- भारती शर्मा,
प्रभारी प्राचार्य, संदीपनी स्कूल (सीएम राइज), जावद

सेवा की अनूठी मिसाल : अरुल अशोक अरोरा व श्री सांवलिया भक्त मण्डल की यात्रा में भोजन और डॉक्टरी टीम रही साथ, रचा नया इतिहास

आस्था का सैलाब : सांवरा सेठ की भक्ति में डूबा नीमच

भजन संध्या और जयकारों के बीच बढ़ती पदयात्रा : निम्बाहेड़ा से आज धाम पहुंचेंगे हजारों श्रद्धालु

नीमच (निप्र)। नीमच शहर में बुधवार को श्री सांवलिया सेठ पैदल यात्रा शुरू हुई, जो आज पांच फरवरी दोपहर बाद चित्तोडगढ जिले के मंफडिया धाम पर पहुंचेगी। पैदल यात्रा में भक्ति की ऐसी सुनामी आई कि हर वर्ग सांवरामय हो गया। पैदल यात्रा में आस्था का सैलाब ऐसा उमडा कि सांवरिया सेठ पहुंच मार्ग वाले रास्ते भी छोटे पड़ गए। युवा समाजसेवी अरूल अशोक अरोरा का धर्म के प्रति लगाव ने इस वर्ष इतिहास रच दिया। महिलाओं से लेकर बडे बुजुर्ग सभी इस पैदल यात्रा में सांवलिया सेठ के जयकारें लगाते हुए चल रहे थे। एक तरफ जयकारों की गूंज नजर आई तो दूसरी तरफ सांवरा सेठ के भक्तों का स्वागत करने के लिए लोग इंतजार करते हुए नजर आएं। दिव्य रथ पर सवार होकर सांवलिया सेठ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए चल रहे थें। आयोजक अरूल अरोरा और श्री सांवलिया मित्र मंडल की व्यवस्थाओं से आम भक्तजन गदगद दिखाई दिए। चाय पानी से लेकर भोजन और चिकित्सकों की टीम यात्रा के साथ चल रही है।

नीमच शहर के लायंस चौराहे पर बुधवार सुबह करीब साढे दस बजे पैदल यात्रा की शुरूआत हुई। पैदल यात्रा में फूलों श्रृंगारित रथ में श्री सांवरा सेठ की प्रतिमा विराजित की गई। दिव्य रथ में विराजित श्री सांवलिया सेठ की विद्वान प्रकांड पंडित आचार्य विक्रम शर्मा शास्त्री द्वारा विधि विधान से अलसुबह पूजा अर्चना करवाई गई। जब तक हजारों लोग पैदल यात्रा में जुड चुके थे। शहर के लायंस पार्क से डीजे की धुन और बैंड बाजों के साथ पैदल यात्रा की शुरूआत हुई।

शहर के गोमोबाई रोड, कलेक्ट्रेट चौराहे, डूंगलावदा, कनावटी, जावद फंटा, सगराना, घंसूडी चौराहे, नयागांव सहित 100 से अधिक जगहों पर पैदल यात्रा का स्वागत किया गया।

सर्व समाज ने किया स्वागत

सकल ब्राह्मण समाज, अग्रवाल समाज, जैन समाज, क्षत्रीय/राजपूत, यादव समाज, अहीर समाज, पार्षद दल नीमच नगरपालिका, गुर्जर समाज, ग्वाला समाज, पंजाबी समाज, बंजारा समाज, वैश्य समाज, स्वर्णकार समाज, कुचबंदिया समाज, माली समाज, राठौर समाज, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, महोश्वरी समाज, साईं बाबा मित्र मंडल, कालू बैरागी मित्र मंडल कनावटी, सायाजी होटल कनावटी, फूलमाली सैनी, प्रेस क्लब, बजरंग दल, नीमच रेडिमेट गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन, केटीवी मित्र मंडल, हेल्पिंग हेंड संस्था, महाकालेश्वर उज्जैन पुजारी मंगलेशजी शर्मा, जायसवाल समाज सहित सर्व समाज के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारियों ने श्री सांवलिया सेठ पैदल यात्रा का जगह-जगह स्वागत किया । विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर मंच लगाकर पुष्प वर्षा कर पैदल यात्रा का स्वागत किया गया।

श्री सांवरिया सेठ पैदल यात्रा में भक्तों ने दिखाई आस्था, उमड़े हजारों लोग

नीमच (निप्र) । नीमच के युवा समाजसेवी अरूल अरोरा की सनानत धर्म के प्रति गहरी आस्था ने श्री सांवरिया सेठ पैदल यात्रा में भक्ति की सुनामी ला दी। चार फरवरी नीमच से शुरू हुई पैदल यात्रा का गुरूवार दोपहर को मंडफिया धाम में समापन हुआ। श्री सांवरिया सेठ को महाप्रसादी का भोग लगाया गया।

विकसित भारत की उड़ान : बजट 2026 के आर्थिक संकल्प

ललित गर्ग

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत नवीन केंद्रीय बजट को यदि समग्र दृष्टि से देखा जाए तो यह केवल एक वार्षिक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'विकसित भारत 2047' के स्वप्न की ठोस आधारशिला के रूप में सामने आता है। यह बजट उस रिफॉर्म एक्सप्रेस की तरह है जो बीते वर्षों में चली आर्थिक सुधारों की पटरियों पर तेज गति से दौड़ते हुए अब भारत को उच्च विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई ऊँचाइयों की ओर ले जाने का दावा करता है। तुलनात्मक, विवेचनात्मक और समीक्षात्मक दृष्टि से यह बजट पूर्ववर्ती बजटों की निरंतरता को बनाए रखते हुए कई नए आयाम भी जोड़ता है, जो इसे ऐतिहासिक और भविष्यगामी बनाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों के बजटों की तुलना में यह बजट अधिक आत्मविश्वास के साथ सामने आता है। महामारी, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बीच भारत ने जिस आर्थिक मजबूती का प्रदर्शन किया है, उसका आत्मविश्वास इस बजट में स्पष्ट झलकता है। जहां पूर्व बजटों में संकट प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को संभालने पर अधिक जोर था, वहीं यह बजट विकास की ऊंची उड़ान के लिए रनवे तैयार करता दिखता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' का मंत्र यहां नारे से आगे बढ़कर नीतिगत संरचना का रूप लेता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की दृष्टि विशेष रूप से विवेचनात्मक है। चिकित्सा अवसंरचना के विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और डिजिटल हेल्थ के माध्यम से गांव-गांव तक चिकित्सा सुविधाएं पहुँचाने की दिशा में किए गए प्रावधान यह संकेत देते हैं कि सरकार स्वास्थ्य को केवल खर्च नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश मान रही है। यदि पिछले दशक के बजटों से तुलना की जाए तो स्वास्थ्य पर आवंटन और दृष्टिकोण दोनों में गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देता है। यह बदलाव भारत को न केवल स्वस्थ समाज की ओर ले जाने वाला है, बल्कि उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि को भी दीर्घकाल में मजबूती देगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट की आत्मा दूरदर्शी है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा,

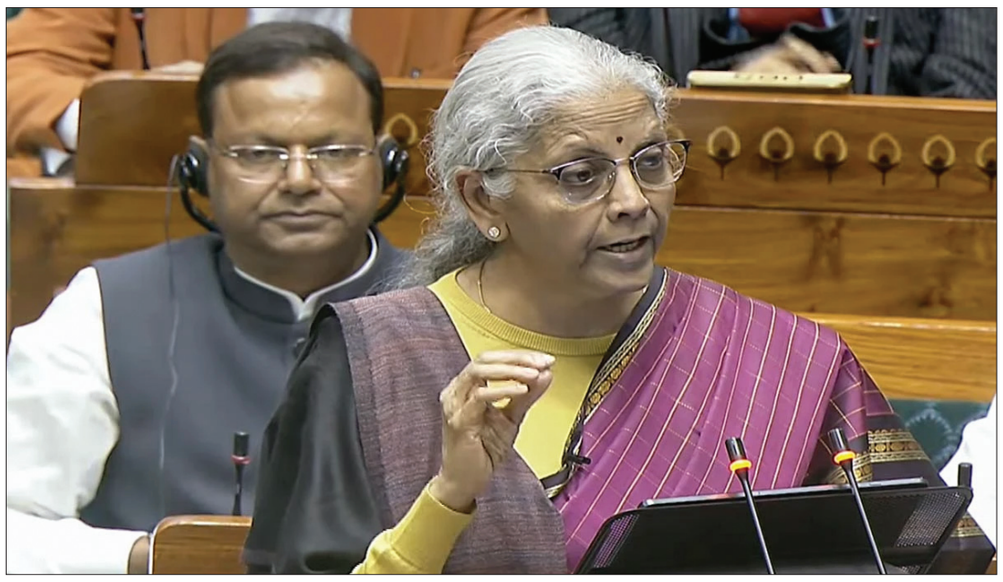

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों से जुड़ी शिक्षा पर बल यह दर्शाता है कि सरकार भविष्य के भारत के लिए आज के युवाओं को तैयार करना चाहती है। पूर्ववर्ती बजटों में शिक्षा पर खर्च की चर्चा होती थी, लेकिन इस बजट में शिक्षा को रोजगार और नवाचार से जोड़ने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ यह बजट तुलनात्मक रूप से अधिक परिपक्व और व्यावहारिक प्रतीत होता है।

विकास की दृष्टि से यह बजट 'इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस समावेशन' का मॉडल प्रस्तुत करता है। रेलवे कॉरिडोरों के विकास, लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाने, सड़क, बंदरगाह और शहरी अवसंरचना में निवेश को जिस तरह प्राथमिकता दी गई है, वह भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत हिस्सा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सात रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा केवल परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं, बल्कि औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन का माध्यम भी है। यदि इसे पिछले बजटों से जोड़कर देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि सरकार अब बुनियादी ढांचे को विकास का इंजन मानकर लगातार गति दे रही है।

ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट विशेष उल्लेख के योग्य है। कृषि, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई, किसान कल्याण और ग्रामीण उद्यमिता से जुड़े प्रावधान यह संकेत देते हैं कि गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की मंशा केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। मेडिकल सुविधाओं, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण भारत में जीवन की गुणवत्ता सुधरने की संभावना बढ़ती है। यह आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसमें गांव मजबूत होंगे तो देश स्वतः मजबूत होगा।

नारी शक्ति के सशक्तिकरण के संदर्भ में भी बजट का दृष्टिकोण तुलनात्मक रूप से व्यापक है। महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला उद्यमिता, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े विशेष प्रावधान यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। गरीबों और वंचित वर्गों के लिए लक्षित योजनाएं इस बजट को सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी संतुलित बनाती हैं। समीक्षात्मक रूप से देखा जाए तो यह बजट कल्याण और विकास के बीच संतुलन साधने का प्रयास करता है, जो किसी भी दीर्घकालिक आर्थिक नीति की अनिवार्य शर्त है।

युवाओं के लिए यह बजट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप, नवाचार, स्किल इंडिया, रोजगार सृजन और नई तकनीकों में निवेश युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करता है। यदि इसे आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के संदर्भ में देखा जाए तो यह भी स्पष्ट होता है कि बजट में क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक यथार्थ का भी ध्यान रखा गया है। हालांकि आलोचक इसे चुनावी बजट कह सकते हैं, लेकिन विवेचनात्मक दृष्टि से यह कहना अधिक उचित होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बजट का जन-आकांक्षाओं से जुड़ा होना स्वाभाविक है, बशर्ते वह दीर्घकालिक विकास को बाधित न करे। इस बजट में दीर्घकालिक दृष्टि और तात्कालिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन दिखाई देता है। समीक्षात्मक रूप से यह स्वीकार करना होगा कि किसी भी बजट की सफलता केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन से तय होती है। संसाधनों की उपलब्धता, राज्यों के साथ समन्वय और पारदर्शी प्रशासन इस बजट की वास्तविक परीक्षा होंगे। फिर भी, तुलनात्मक दृष्टि से यह बजट भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव प्रतीत होता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत के विकास की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। यह वर्तमान की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भविष्य की संभावनाओं के लिए रास्ता तैयार करता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसंरचना, ग्रामीण विकास, नारी शक्ति और युवाओं को केंद्र में रखकर यह बजट 'विकसित भारत 2047' की दिशा में एक सशक्त कदम है। यदि इसे निरंतर सुधार, जवाबदेही और समावेशी क्रियान्वयन का साथ मिला, तो यह बजट इतिहास में केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव के रूप में याद किया जाएगा।

संपादकीय

लोकलुभावन की बजाय बचत का रास्ता चुना सरकार ने

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जब अपना 9वां बजट भाषण पढ़ना शुरू किया तो सत्ता के गलियारों में चर्चा थी कि क्या सरकार आगामी विधानसभा चुनावों या वैश्विक मंदी की आहट के बीच कोई बड़ा धमाका करेगी, लेकिन डेढ़ घंटे के बाद यह स्पष्ट हो गया कि वित्तमंत्री ने लोकलुभावन के बजाय बचत का रास्ता चुना। राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर सीमित रखना बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन शेयर बाजार की मायूसी यह सवाल खड़ा करती है कि क्या देश की वित्तीय सेहत सुधारने की कवायद में हम विकास की रफ्तार को नजरअंदाज कर रहे हैं?

वित्तमंत्री ने राजकोषीय घाटे को 4.4 प्रतिशत पर लाकर एक कड़ा संदेश दिया कि वह देश को कर्ज के जाल से बाहर निकालना चाहती हैं। कम घाटे का अर्थ है कि सरकार को बाजार से कम उधार लेना पड़ेगा। इससे निजी क्षेत्र के लिए कर्ज की उपलब्धता बढ़ेगी और ब्याज दरों में गिरावट की संभावना बनेगी। यह वैश्विक रेटिंग एजेंसियों, जैसे मूडीज और फिच को सकारात्मक संकेत देता है, जिससे विदेशी निवेश का मार्ग प्रशस्त होता है। हालांकि, इसका नकारात्मक पक्ष यह है कि घाटे को कम करने के लिए सरकार को अपने खर्चों पर लगाम लगानी पड़ी है। यही वह बिंदु है, जहां बाजार और सरकार के हित आपस में टकरा रहे हैं। वित्तमंत्री से शेयर बाजार को उम्मीद थी कि वो अर्थव्यवस्था में नकदी बढ़ाएंगी, लेकिन बजट ने इसके उल्ट काम किया। बाजार की निराशा के तीन मुख्य बिंदु हैं। पहला, पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखने को मिली थी। इस बार इसे केवल 10 प्रतिशत बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया। निवेशकों को डर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश कम होने से सीमेंट, स्टील और लॉजिस्टिक कंपनियों की ग्रोथ सुस्त पड़ जाएगी। दूसरा, मध्यम वर्ग और ग्रामीण आबादी के लिए किसी बड़ी टैक्स कटौती या नकद हस्तांतरण की अनुपस्थिति ने बाजार को चौंका दिया। बाजार का मानना है कि जब तक आम आदमी की जेब में अतिरिक्त पैसा नहीं आएगा, तब तक ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी जैसे सेक्टरों में मांग नहीं बढ़ेगी। तीसरा, बाजार किसी बड़ी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की उम्मीद कर रहा था, जैसे कि विनिवेश का नया लक्ष्य या बैंकिंग क्षेत्र में निजीकरण की स्पष्ट समय सीमा। इन पर चुप्पी ने निवेशकों को मुनाफावसूली के लिए उकसाया। वित्तमंत्री ने नए इनकम टैक्स कानून के जरिए जटिलताओं को कम करने का प्रयास तो किया है, लेकिन करदाताओं के लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं दी। स्टैंडर्ड डिडक्शन में मामूली बढ़ोतरी और स्लैब में छोटे बदलावों को बाजार ने अपर्याप्त माना। निवेशकों को उम्मीद थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर कुछ राहत मिल सकती है, जो नहीं मिली। हालांकि, वित्त मंत्री का बचाव यह हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की अस्थिर कीमतों के बीच बड़ी घोषणाएं करना जोखिम भरा हो सकता था।

चिंतन-मनन

सन्मार्ग की प्रवृत्ति

उत्तम कार्य की कार्य प्रणाली भी प्रायः उत्तम होती है। दूसरों की सेवा या सहायता करनी है, तो प्रायः मधुर भाषण, नम्रता, दान, उपहार आदि द्वारा उसे संतुष्ट किया जाता है। परन्तु कई बार इसके विपरीत क्रिया-प्रणाली ऐसी कठोर, तीक्ष्ण एवं कटु बनानी पड़ती है कि लोगों को भ्रम हो जाता है कि कहीं यह दुर्भाव से प्रेरित होकर तो नहीं किया गया। ऐसे अवसरों पर वास्तविकता का निर्णय करने में बहुत सावधानी बरतने पड़ती है। सीधे-सादे अवसरों पर सीधी-सादी प्रणाली से भली प्रकार काम चल जाता है। भूखे, प्यासे की सहायता करनी है, तो वह कार्य अन्न-जल देने के सीधे-सादे तरीके से चल जाता है। किसी दुःखी या अभावग्रस्त को अभीष्ट वस्तुएं देकर उसकी सेवा की जा सकती है। धर्मशाला, कुआं, पाठशाला, अनाथालय, औषधालय आदि द्वारा लोकसेवा की जा सकती है। ऐसे कार्य निश्चय ही श्रेष्ठ हैं और उनकी आवश्यकता व उपयोगिता सर्वत्र स्वीकारी जा सकती है। परन्तु कई बार ऐसी सेवा की भी बड़ी आवश्यकता होती है, जो प्रत्यक्ष में बुराई मालूम पड़ती है और उसे करने वाले को अपयश ओढ़ना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाने का साहस हर किसी में नहीं होता।

दुष्ट और अज्ञानियों को उस मार्ग से छुड़ाना, जिस पर वे बड़ी ममता और अहंकार के साथ प्रवृत्त हो रहे हैं, साधारण काम नहीं है। सीधे आदमी की भूल ज्ञान से, तर्क से, समझाने से सुधर जाती है पर जिनकी मनोभूमि अज्ञानान्धकार से कलुषित हो, साथ ही जिनके पास कुछ शक्ति भी है, वे ऐसे मदान्ध हो जाते हैं कि सीधी-सादी क्रिया-प्रणाली का उन पर प्रायः कुछ असर नहीं होता। मनुष्य शरीर धारण करने पर भी जिनमें पशुत्व की प्रधानता है, दुनिया में उनकी कमी नहीं है। उन्हें ज्ञान, तर्क, नम्रता, सज्जनता, सहनशीलता से अनीति के दुःखदाई मार्ग से पीछे नहीं हटाया जा सकता। पशु केवल दो चीजें पहचानता है- एक लोभ, दूसरा भय। दाना, घास खिला उसे ललचा कर कहीं भी ले जाइए, वह पीछे-पीछे चलेगा या लाठी का डर दिखा जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं।

किसान धैर्य रखें, हर खेत का होगा सर्वे : देवड़ा

ओलावृष्टि का कहर : डिप्टी सीएम देवड़ा ने खेतों में उतर कर देखा फसलों का नुकसान

मन्दसौर निप्र। मालवा अंचल में हुई भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को मंदसौर जिले के प्रभावित गांवों का सघन दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। खेतों की मेड़ पर पहुंचकर फसलों की बर्बादी देख डिप्टी सीएम ने किसानों को ढांढस बंधाया और स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ अन्नदाता के साथ खड़ी है।

अफीम नुकसान के लिए केंद्र से करेंगे चर्चा – विशेष रूप से अफीम की फसल को हुए नुकसान पर देवड़ा ने कहा कि नारकोटिक्स विभाग की टीमें भी मौके पर निरीक्षण कर रही हैं। अफीम उत्पादकों को राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार से चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही, उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि फसल बीमा का शत-प्रतिशत लाभ दिलाने के लिए भी प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

प्रशासनिक अमला रहा मौजूद – निरीक्षण के दौरान जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित, अपर कलेक्टर एकता जायसवाल, मल्हारगढ़ एसडीएम सहित राजस्व और कृषि विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक भी किसान सर्वे से वंचित नहीं रहेगा।

खेतों का जाना हाल, अफीम की बर्बादी पर जताई चिंता

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने ग्राम कितुखेड़ी, गोपालपुर, लोढ़ाखेड़ा, झारड़ा, अड़मालिया और किशनगढ़ का दौरा किया। उन्होंने खेतों में पहुंचकर अफीम, गेहूं, चना, चिया और अलसी की फसलों को हुए नुकसान का भौतिक सत्यापन किया। किसानों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'आप चिंता न करें, अधिकारी हर खेत तक पहुंचेंगे। वास्तविक स्थिति के आकलन के लिए स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं और सर्वे कार्य युद्धस्तर पर जारी है।

हर पंचायत में लगेगा एक सूक्ष्म खाद्य उद्योग

कलेक्टर ने दिए पीएमएफएमई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश

नीमच (निप्र)। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के तहत अब नीमच जिले की हर पंचायत में कम से कम एक उद्योग स्थापित किया जाएगा। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित ए.पी.सी. समूह, कृषि, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक में यह लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों और किसानों को प्रेरित कर उन्हें उद्यमी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मत्स्य पालकों का बनेगा एफपीओ – मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर ने विभाग को इसी माह मत्स्य पालकों का एक एफपीओ (कृषक उत्पादक संगठन) गठित करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य जिले के मत्स्य पालकों को संगठित कर उन्हें आधुनिक व्यवसाय से जोड़ना और उनकी आय में वृद्धि करना है।

धार्मिक स्थलों के आसपास महकेंगे फूल – उद्यानिकी विभाग को निर्देशित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि आंतरी माता और भादवा माता जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के क्लस्टर में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाए।

डिफॉल्टर किसानों के लिए चलेगा विशेष अभियान

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.पी. नागदा को सख्त निर्देश दिए कि डिफाल्टर किसानों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि किसानों को बकाया राशि जमा करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे पुनः केसीसी, कृषि ऋण और खाद-बीज जैसी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

भाजपा पार्षद की पत्नी की चाकू गोदकर हत्या

मंदसौर (निप्र)। शहर के अभिनंदन क्षेत्र में गुरुवार शाम सरेराह एक सनसनीखेज वारदात हुई। वार्ड क्रमांक 15 से भाजपा पार्षद शाहिद मेव की पत्नी रुबीना (35) की दो अज्ञात बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हमला उस समय हुआ जब रुबीना अपने मायके से लौटकर ऑटो में बैठ रही थी। पुलिस ने मामले में पारिवारिक रंजिश की आशंका जताई है और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी है।

पारिवारिक रंजिश का संदेह, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस – प्रारंभिक जांच में पुलिस इस हत्याकांड के पीछे पारिवारिक कलह को मुख्य वजह मान रही है। सूत्रों के मुताबिक, साहिल नामक एक युवक पर हत्या का संदेह जताया जा रहा है, जो परिवार का ही करीबी बताया जा रहा है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज जुटाए हैं ताकि आरोपियों की शिनाख्त की जा सके।

7 महीने पहले हुई थी तीसरी शादी – पुलिस ने बताया कि पार्षद शाहिद मेव ने करीब सात महीने पहले ही रुबीना से निकाह किया था। यह शाहिद की तीसरी शादी थी। रुबीना के पहले से दो बच्चे (एक बेटा और एक बेटी) हैं। मृतका के भाई पीरु शाह ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा।

ऑटो में बैठते ही ताबड़तोड़ वार

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वारदात शाम करीब साढ़े पांच बजे की है। रुबीना अपने पिता के घर से किराए के मकान पर जाने के लिए ऑटो में सवार हो रही थी। इसी दौरान अपाचे बाइक पर दो युवक वहाँ पहुँचे। बाइक से उतरे एक युवक ने रुबीना पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ कई हमले किए। लहूलुहान हालत में रुबीना को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सेन समाज का परिचय सम्मेलन : 364 युवक-युवतियों ने मंच से दिया परिचय, 28 अप्रैल को होगा सामूहिक विवाह

नीमच । जिला सेन समाज संगठन ने तीसरे राष्ट्रीय युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजन किया। टाउनहॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से समाज के लोग जुटे, जहां युवाओं ने अपने जीवनसाथी की तलाश में अपनी खूबियां साझा कीं। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य न केवल योग्य रिश्तों को जोड़ना था, बल्कि समाज में एकता और सादगी को बढ़ावा देना भी रहा।

दीप प्रज्वलन और संस्कारों पर दिया जोर – समारोह की शुरुआत समाज के आराध्य देव सेन महाराज के चित्र पर माल्यार्पण और सरस्वती वंदना के साथ हुई। इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ समाजसेवियों ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि बदलते दौर में भी पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों का महत्व कम नहीं हुआ है।

उन्होंने ऐसे आयोजनों को आधुनिक समय की जरूरत बताया, जहां एक ही छत के नीचे शिक्षित और योग्य जीवनसाथी चुनने का अवसर मिलता है।

364 युवाओं ने कराया पंजीयन – आयोजन समिति ने बताया कि इस सम्मेलन को लेकर समाज में काफी उत्साह देखा गया। कुल 364 युवक-युवतियों ने परिचय के लिए अपना नाम दर्ज कराया।

इनमें नीमच और मालवा क्षेत्र के अलावा राजस्थान के सीमावर्ती जिलों और मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों के प्रतिभागी भी अपने परिजनों के साथ शामिल हुए। मंच से बारी-बारी युवाओं ने अपनी शिक्षा, व्यवसाय और रुचियों की जानकारी दी।

कुंडली मिलान और चर्चा की विशेष व्यवस्था – अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हॉल में विशेष इंतजाम किए गए थे। रिश्तों की शुरुआती बातचीत और कुंडली मिलान के लिए अनुभवी पंडितों को भी आमंत्रित किया गया था। कई परिवारों ने मंच पर परिचय के बाद अलग बैठकर प्रारंभिक चर्चा की और रिश्तों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। पूरा कार्यक्रम बेहद अनुशासित और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ।

28 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेल – सम्मेलन के समापन पर संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि 28 अप्रैल को सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। पदाधिकारियों ने समाज के लोगों से अपील की है कि वे अभी से इस आयोजन की तैयारियों में जुट जाएं ताकि अधिक से अधिक जोड़ों का विवाह फिजूलखर्ची से बचकर सादगीपूर्ण तरीके से कराया जा सके।

सांसद सुधीर गुप्ता के सवाल पर केंद्र सरकार का बड़ा जवाब

सड़क हादसों में घायलों को मिलेगा 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज

नई पहलः देशभर में लागू हुई 'कैशलेस उपचार योजना-2025' दुर्घटना के 7 दिनों तक मिलेगी नकद रहित उपचार की सुविधा

मंदसौर/नीमच, निप्र। ***सड़क दुर्घटनाओं में समय पर इलाज न मिलने के कारण होने वाली मौतों को रोकने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मंदसौर-नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा लोकसभा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि देश में 'सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना-2025' को अधिसूचित कर दिया गया है।***

डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा उपचार – योजना की तकनीकी बारीकियों को साझा करते हुए बताया गया कि इसे ई-डीएआर (इलेक्ट्रॉनिक दुर्घटना रिपोर्ट) और आयुष्मान भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म (TMS 2.0) से जोड़ा गया है। इससे इलाज, दावों का निपटान और भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। गंभीर मामलों में पीड़ितों को निर्धारित अस्पतालों में 24 से 48 घंटे तक 'स्थिरीकरण उपचार' देने का भी प्रावधान किया गया है ।

MVAF से होगा अस्पतालों का भुगतान – संसद में दिए गए जवाब के अनुसार, अस्पतालों को किए जाने वाले भुगतान की व्यवस्था मोटर वाहन दुर्घटना निधि (MVAF) के माध्यम से की जाएगी।

जिन वाहनों का बीमा होगा, उनके मामलों में भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जाएगा, जबकि अन्य मामलों में सरकारी सहायता से भुगतान सुनिश्चित होगा। सांसद सुधीर गुप्ता की इस पहल से क्षेत्र सहित देशभर के सड़क दुर्घटना पीड़ितों को बड़ा संबल मिलेगा।

योजना की खास बातें

- **नकद रहित इलाजः** अस्पताल में भर्ती होने पर जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं।
- **समय सीमाः** दुर्घटना के पहले 7 दिनों तक उपचार की गारंटी।
- **पात्रताः** सभी प्रकार के सड़क हादसों के पीड़ित इसके दायरे में।
- **त्वरित राहतः** आयुष्मान भारत के नेटवर्क वाले अस्पतालों में मिलेगी सुविधा।

»»» 7 दिनों तक 1.5 लाख का कवर

सांसद गुप्ता ने मंत्रालय से देशव्यापी कैशलेस उपचार योजना और उसकी विशेषताओं की जानकारी मांगी थी। जवाब में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत इस योजना को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत सड़क हादसे में घायल प्रत्येक व्यक्ति को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का नकद रहित (कैशलेस) उपचार प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा सभी श्रेणी की सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मान्य होगी।

बेहद अलग है जूलॉजी में कॅरियर

जूलॉजी में कॅरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करना होगा। 12वीं के बाद बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग है, जो प्रकृति में मौजूद विभिन्न तरह के प्राणियों के बारे में गहराई से जानने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोग जूलॉजी में अपना करियर देख सकते हैं। जूलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है, जो मछली, सरीसृप, पक्षियों और स्तनधारियों सहित जानवरों का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह संरचना, शरीर रचना, विशेषताओं, व्यवहार, वितरण, पोषण की विधि, शरीर विज्ञान, आनुवंशिकी और पशु प्रजातियों के विकास को शामिल करता है। जूलॉजी का अध्ययन करते समय आप समुद्री जीवों, चिड़ियाघर के जानवरों और जंगली और यहां तक कि घरेलू पालतू जानवरों सहित जानवरों के जीव विज्ञान और आनुवंशिकी का अध्ययन करते हैं। ऐसे में अगर आप भी इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो बतौर जूलॉजिस्ट बनकर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में

क्या होता है काम

एक जूलॉजिस्ट का मुख्य काम जानवरों के व्यवहार, विशिष्ट विशेषताओं और उनमें विकासवादी प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। जूलॉजिस्ट को पशु जीवविज्ञानी या वैज्ञानिक भी कहा जाता है। यह एक बेहद विस्तृत क्षेत्र है और विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले जूलॉजिस्ट को अलग-अलग नामों से जाना जाता है। मसलन, पक्षियों के अध्ययन में विशेषज्ञता वाले जूलॉजिस्ट्स को ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है, वहीं मछली का अध्ययन करने वाले को आइकथोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक इसी तरह, जो जूलॉजिस्ट्स जो उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं उन्हें हेरपेटोलॉजिस्ट नाम से जाना जाता है और स्तनधारियों से जुड़े लोगों को मैमलॉजिस्ट कहा जाता है। उनके कार्यक्षेत्र में जानवरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीड़े, मछलियों और कीड़े के पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें विभिन्न स्थानों पर प्रबंधित करना है। जूलॉजिस्ट डीएनए पहचान सहित उच्च तकनीक के सभी प्रकार के क्षेत्र में और प्रयोगशाला में काम करते हैं, और वे जानकारी के डेटाबैंक विकसित करते हैं।

योग्यता

कॅरियर एक्सपर्ट की मानें तो जूलॉजी में कॅरियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले जीव विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान में ज्ञान प्राप्त करना होगा। 12वीं के बाद बैचलर की डिग्री हासिल करने के बाद आप इस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। हालांकि आप इस क्षेत्र में बैचलर की डिग्री के बाद मास्टर डिग्री या डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं।

व्यक्तिगत कौशल

एजुकेशन एक्सपर्ट कहते हैं कि जूलॉजी के क्षेत्र में कॅरियर देख रहे छात्रों का बेहद साहसी होना जरूरी है और उनके जीवन में डर के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समर्पित, स्वतंत्र और मेहनती भी होना चाहिए। उन्हें विभिन्न लोगों के साथ काम करना आना चाहिए। चूंकि वैज्ञानिक अक्सर शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, इसलिए उनके पास प्रभावी लिखित और मौखिक संचार क्षमताएं होनी चाहिए। वह अपना अधिकांश समय जानवरों के साथ बिताते हैं, इसलिए उन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें काटने, खरोंचने आदि जैसे हमलों के लिए हरदम मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए और चोटों को सहने की क्षमता होनी चाहिए। जूलॉजी के क्षेत्र में आपको कई घंटों तक काम करना पड़ सकता है, जो वास्तव में आपके लिए थकाऊ हो सकता है।

संभावनाएं

बतौर जूलॉजिस्ट आप चिड़ियाघर, वाइल्डलाइफ सर्विस, बोटेनिकल गार्डन, कंसर्वेशन आर्गेनाइजेशन, नेशनल पार्क, यूनिवर्सिटी व लेबोरेटरीज आदि में काम कर सकते हैं। जहां चिड़ियाघर व म्यूजियम में वे बतौर एजुकेटर या क्यूरेटर अपना कॅरियर आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं आप स्कूल या कॉलेज में टीचर्स या रिचर्सर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। वहीं अपना शोध पूरा कर लेने के बाद आप एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में भी आगे कार्य कर सकते हैं। इसी तरह एनिमल रिहैबिलिटेटर्स या बतौर कंसर्वेशनिस्ट भी आप अपना उज्जवल भविष्य देख सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आपका वेतन शिक्षा, अनुभव, कार्य की प्रकृति व स्पेशलाइजेशन के आधार पर निर्भर करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी आमदनी हो सकती है। शुरूआती दौर में आप 10000 से 15000 रूपए महीना आसानी से कमा सकते हैं। वहीं कुछ समय के पश्चात आपकी आमदनी 25000 रूपए प्रतिमाह या इससे अधिक भी हो सकती है। अगर कुछ वर्षों के अनुभव के पश्चात आप विदेश में काम करते हैं तो आप यकीनन लाखों में कमा सकते हैं।

लेखन के क्षेत्र में बनाएं कॅरियर

ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जिन्हें लिखना बहुत पसंद होता है। लेखन की कई विधाएं हैं, इन्हीं में से एक है क्रिएटिव राइटिंग। लेखन के क्षेत्र की यह विधा बेहद कलात्मक है। इस क्षेत्र से जुड़े लोग वास्तव में रचनात्मक लेखक हैं, जिन्हें लोग उपन्यासकार, कवि, गीतकार आदि विभिन्न नामों से जानते हैं। क्रिएटिव राइटर्स के पास लेखन में जादुई शक्ति होती है और अपने काम के माध्यम से, वे पाठकों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें परेशान, घृणित, मंत्रमुग्ध या खुश कर सकते हैं। आमतौर पर लोग इस काम को आसान मानते हैं, जबकि लेखन बनाना एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक शोध और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अगर आप भी लेखन में अपनी रूचि रखते हैं तो इस क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा सकते हैं

क्या है क्रिएटिव राइटिंग

रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें एक लेखक का उद्देश्य गद्य और काव्य छंदों के माध्यम से अपनी भावनाओं, भावनाओं, कल्पनाशील विचारों और विचारों को व्यक्त करना है। विभिन्न तरह के लेखन जैसे उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, आत्मकथा, पटकथा लेखन, कॉपी लेखन आदि को रचनात्मक लेखन कहा जाता है। रचनात्मक लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक दुनिया के चित्र बनाने के लिए बहुत अधिक कल्पना, अवलोकन और एक जन्मजात क्षमता की आवश्यकता होती है। विभिन्न विषयों और शैलियों पर लेख पढ़कर एक अच्छा लेखक बन सकता हैय हर तरह से जीवन का अनुभव करना और बहुत सारे मुहावरों, लहजों और स्थानीय भावों को सीखना और सुनना। वैसे तो क्रिएटिव राइटिंग कुछ लोगों को जन्मजात उपहार में मिलती हैं, लेकिन रचनात्मक लेखन में कोर्स करके कोई भी अपने लेखन कौशल में सुधार कर सकता है।

योग्यता

कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार

रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में किसी औपचारिक शिक्षा की विशेष आवश्यकता नहीं है। आपकी कल्पना, अवलोकन और रचनात्मकता के साथ लिखने की क्षमता ही आपके भविष्य के मार्ग प्रशस्त करती है। हालांकि अंग्रेजी साहित्य या पत्रकारिता और संचार में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके कॅरियर की राह को आसान बनाती है।

में एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आपके कॅरियर की राह को आसान बनाती है। वैसे भारत में कुछ संस्थान रचनात्मक लेखन में शार्ट टर्म कोर्स कराते हैं और इन पाठ्यक्रम में आवेदन करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकंडरी या 10+2 होनी चाहिए। इन पाठ्यक्रमों की न्यूनतम अवधि एक वर्ष है।

व्यक्तिगत गुण

कॅरियर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक क्रिएटिव राइटर को कल्पनाओं के आकाश में विचरने के साथ-साथ उसे कागज पर भी बेहतरीन तरीके से उतारने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर पढ़ने व नई चीजों को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, ताकि वह अपने शब्दकोश को अधिक मजबूत बना सके। चूंकि इन दिनों लेखन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगता है। इसलिए उसे कंप्यूटर का ज्ञान होना व इंटरनेट में आवश्यक सामग्री खोजने की कला आनी चाहिए। इसके अलावा उसके भीतर ऑर्ब्जवेशन स्किल्स व कम्युनिकेशन स्किल्स भी मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जब एक लेखक अपने या दूसरों के अनुभवों के पन्ने पर उतारता है तो उसका एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन के जरिए उसके लेखन में भी विविधता को आसानी से देखा जा सकता है।

संभावनाएं

क्रिएटिव राइटर्स के पास अवसरों की कोई कमी नहीं है। कॅरियर एक्सपर्ट की मानें तो आप अपनी रूचि के अनुसार उपन्यास से लेकर संस्मरण, कविता, गीत, साइंस फिक्शन, रोमांस, स्क्रिप्ट, नाटक, यात्रा-वृत्तांत आदि लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पत्र-पत्रिकाओं और समाचार पत्रों आदि के लिए रिपोर्ट, साक्षात्कार, सुविधाएँ, आलोचना और समीक्षाएं लिख सकता है। इसके अलावा, रचनात्मक लेखक वेब साइटों के लिए भी कंटेंट लिख सकते हैं या प्रिंट मीडिया के लिए लेख बना सकते हैं। आप किसी एक संस्थान से जुड़कर काम कर सकते हैं या फिर अलग-अलग संस्थानों के लिए फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं।

आमदनी

इस क्षेत्र में आमदनी आपके अनुभव व कौशल पर निर्भर करती हैं। शुरूआती दौर में एक क्रिएटिव राइटर आठ से दस हजार रूपए प्रतिमाह कमा सकता है। इसके बाद अनुभव बढ़ने के बाद आपका काम व आमदनी दोनों बढ़ती चली जाती है।

प्रमुख संस्थान

- इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली
- डॉ.बाबासाहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद
- नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मीडिया स्टडीज, अहमदाबाद
- कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी

एंट्री इंटरव्यू की तरह एग्जिट इंटरव्यू भी मायने रखता है

एंट्री इंटरव्यू की तरह ही किसी कंपनी का एग्जिट इंटरव्यू भी उतना ही मायने रखता है।नौकरी छोड़ने से पहले एग्जिट इंटरव्यू भले ही मात्र एचआर संबंधी औपचारिकता लगे लेकिन इसका मतलब ये नहीं हैं कि इसके लिए आप कोई तैयारी न करें। इंटरव्यू में अपने जवाबों को तैयार रखकर आप अपने लिए भविष्य में उस कंपनी के दरवाजे हमेशा खुले रख सकेंगे। आइए जानते हैं एग्जिट इंटरव्यू के लिए कुछ जरूरी टिप्सः

सकारात्मक चीजों पर फोकस

एग्जिट इंटरव्यू के संदर्भ को समझना महत्वपूर्ण है और बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए सच बोलना जरूरी है। करियर के इस मोड़ पर आपको सकारात्मक प्रभाव बनाने के लिए सहयोगियों और प्रबंधकों की तारीफ करना चाहिए।

वापसी की इच्छा जताएं

अगर आप अच्छे टर्म के साथ अपने कार्यकाल को ऑफिस में पूरा कर रहे हैं तो इसके लिए आपको वापसी के सारे रास्ते खुल रखने की कोशिश करना चाहिए। हमेशा जुड़े रहने की इच्छा जताएं और वहां के एल्यूमिनी नेटवर्क का हिस्सा बनने को कहें।

आभार व्यक्त करें

ऑर्गनाइजेशन में अपने कार्यकाल को सहज बनाने में मदद करने वालों के प्रति आभार जताना न भूलें। यह केवल मैनेजमेंट को आपके बारे में पॉजिटिवी फील देगा।

माइक्रो पर्सपेक्टिव

अगर आपको अपने किसी साथी या वरिष्ठ प्रबंधक से संबंधित कोई बात रखने की भी है तो उसे सही तरीके से रखें। कुछ अगर कहना आवश्यक भी हो तो उसे माइक्रो पर्सपेक्टिव रखें।

कंस्ट्रक्टिव फीडबैक

आपके कार्यकाल के दौरान ऐसा समय भी रहा होगा जब वहां कलह और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। सुधारात्मक उपायों के साथ ईमानदार प्रतिक्रिया दें।

वकालत करने के लिए जानें बेसिक बातें

सामान्य रूप से लॉ की पढ़ाई के लिए आपका 12वीं पास होना आवश्यक है और यह किसी भी विषय में हो सकता है। इसमें 50 परसेंट मार्क्स ही आवश्यक है और ऐसे में आपकी एज 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में कानून का शासन है। हर चीज कानून के अनुसार चलती है। कानून के अनुसार ही प्रशासन चलता है, कानून के अनुसार ही अदालतों का सिस्टम चलता है।

अदालतों में हम देखते हैं कि कानून के अनुसार ही एक पक्ष दूसरे पक्ष को चुनौती देता है और अदालतों में कानून के जानकार इसके भिन्न पक्षों की व्याख्या भी करते हैं। इन्हीं कानून के जानकारों को हम वकील कहते हैं और वकील बनने के लिए आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ती है। इस पढ़ाई का का प्रथम चरण होता है एलएलबी का, यानी बैचलर आफ लॉ! वैसे कानून की पढ़ाई सिर्फ एक प्रोफेशन भर ही नहीं है, बल्कि यह उन तमाम जरूरतमंद लोगों को सिस्टम के साथ जोड़ने में एक अति महत्वपूर्ण कड़ी है, जो तमाम कारणों से अन्याय के शिकार होते हैं। जिन्हें पता तक नहीं होता है कि उन्हें कानून की जानकारी ना होने के कारण असीमित नुकसान उठाना पड़ा है। सच कहा जाए तो हमारे देश में ला प्रोफेशनल्स की जवाबदेही, किसी भी दूसरे प्रोफेशन से अधिक हो जाती है, क्योंकि यह कानून के शासन पर भरोसा पैदा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सामान्य रूप से लॉ की पढ़ाई के लिए आपका 12वीं पास होना आवश्यक है और यह किसी भी विषय में हो सकता है। इसमें 50 परसेंट मार्क्स ही आवश्यक है और ऐसे में आपकी एज 20 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको सीएलएटी एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कहा जाता है और यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एग्जाम में आपसे लॉजिकल रीजनिंग, लीगल, एटीट्यूड, गणित, अंग्रेजी और जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 5 साल के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं।

सामान्यत : पांच साल के इन्टीग्रेटेड कोर्स के एंट्रेंस हेतु 200 अंकों के क्वेश्चन पेपर के लिए डेढ़ घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें इंग्लिश के 30 अंक, सामान्य ज्ञान के 50 अंक, लीगल एप्टीट्यूड के 20 अंक, लीगल रीजनिंग के 20 अंक होते हैं एवं 30 अंकों का एक एस्से भी लिखना होता है।

लॉ करने के बाद आपको इंटर्नशिप का कोर्स करना होता है और इस दौरान आपको काफी कुछ ट्रेनिंग मिलती है। इंटर्नशिप के बाद आपको किसी भी राज्य के स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना होता है और उसके बाद ऑल इंडिया बार कौंसिल का एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है और इसके बाद आप वकील बन जाते हैं।

हालाँकि, ग्रेजुएशन के बाद भी आप लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं और तब यह मात्र 3 साल का होता है। ग्रेजुएशन में भी आपको साधारणतया 50 परसेंट मार्क्स लाना होता है। वैसे एससी/ एसटी कटगरी स्टूडेंट्स के लिए इसमें छूट भी होती है।

लॉ की केटेगरी देखें तो मुख्यत : कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, पेटेंट, एटर्नी, फैमिली लॉ, साइबर लॉ और बैंकिंग ला के रूप को गिनाया जा सकता है और किसी भी विषय में बाद में आप खुद को स्पेशलाइज कर सकते हैं। जैसा कि नाम के साथ ही स्पष्ट है कि पर्टिकुलर फील्ड में आप सम्बंधित क्षेत्र की विशेषज्ञता की हद तक जानकारी लेंगे।

खास बात यह भी है कि एलएलबी के बाद एलएलएम और पीएचडी जैसी विशेषज्ञता भी आप हासिल कर सकते हैं और बाद के दिनों में आप न्यायपालिका की परीक्षा देकर जज बनने की भी कोशिश कर सकते हैं।

लॉ करने के लिए देश भर के कुछ अच्छे कॉलेजों की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु, नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद, नेशनल लॉ इन्स्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल, द वेस्ट बेंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्युरीडिकल साइंस, कोलकाता, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद, डॉ.राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ, राजीव गाँधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, पटियाला, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पटना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लागल स्टडीज, कोच्चि का नाम मुख्य रूप से गिनाया जा सकता है। यूं अधिकांश यूनिवर्सिटीज में यह कोर्स उपलब्ध हैं और देश के तमाम जिलों में आपको ऐसे कॉलेज मिल जायेंगे, जहाँ से आप लॉ में एडमिशन लेकर कानून की समझ बढ़ा सकते हैं। वर्तमान में इस कोर्स के स्कोप की बात करने की जरुरत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल अदालती प्रैक्टिस के अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में, एनजीओ में, बैंकिंग सेक्टर में, सरकार एवं उसके संस्थानों में, स्वतंत्र पत्रकारिता (फ्रीलांस जर्नलिज्म) में, सेना तक में, लॉ फर्म्स के साथ-साथन्यायिक सेवा तक में इसका विस्तार है।

नीमच में बेसहारा गौवंश, अवैध चारा परिवहन पर ज्ञापन

गौ सेवा समिति ने कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग

नीमच । शहर में बढ़ते बेसहारा गौवंश और जिले से बाहर सूखे चारे के अवैध परिवहन के खिलाफ गौ सेवा समिति एवं गौ सेवा दल ने मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। समिति ने गौवंश संरक्षण और गौपालन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

सभी गौवंश की टैगिंग जरूरी – ज्ञापन में शहर में घूम रहे सभी गौवंशों की अनिवार्य टैगिंग करने की बात कही गई। इसका उद्देश्य बीमार या घायल अवस्था में मिलने पर उनके मालिकों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बिना टैग वाले गौवंश को सीधे गौशाला भेजे जाने और टैग किए गए मवेशियों को मालिकों को तभी सुपुर्द किए जाने की मांग की गई, जब वे उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ने का लिखित आश्वासन दें।

सांड और दुर्घटनाओं की समस्या – समिति के अध्यक्ष मिनेश अहीर और पार्थ जोशी ने बताया कि बड़ी संख्या में नंदी (सांड) बेसहारा घूम रहे हैं, जो सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं। इसलिए इनके लिए पृथक गौशाला व्यवस्था की आवश्यकता है।

रबी सीजन में चारे पर नियंत्रण – ज्ञापन में रबी सीजन के दौरान दलालों द्वारा सूखे चारे के अवैध भंडारण और महंगे दामों पर बिक्री का मुद्दा भी उठाया गया। समिति ने शासन स्तर पर चारे की खरीदी और टैग के आधार पर गौपालकों को रियायती दरों पर चारा उपलब्ध कराने की मांग की।

अवैध परिवहन और फैक्ट्री में जलाने पर रोक – समिति ने फैक्ट्रियों में चारा जलाने पर रोक और जिले से बाहर चारे के अवैध परिवहन को रोकने की भी मांग की।

ज्ञापन सौंपते समय समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। उन्होंने "गौवंश बचेगा, देश बचेगा" का नारा लगाया और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की अपनी मांग दोहराई।

अवैध खनिज परिवहन करते तीन वाहन जब्त

नीमच, निप्र। जिला खनिज अधिकारी गजेंद्र सिंह डाबर ने बताया, कि खनिज टीम द्वारा अवैध उत्खनन परिवहन एवं भण्डारण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए नीमच एवं जीरन क्षेत्र में बुधवार को गिट्टी,रेत एवं खण्डा का अवैध परिवहन करते तीन वाहनों को जब्त किया गयाहै। जब्त वाहनों को पुलिस थाना जीरन, नीमच सिटी एवं जावद की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ खडा किया गया है। जब्त वाहनों में रेत ट्राला पंजीयन क्र. आर.जे.27 जी.सी.4635, गिट्टी डंपर एम.पी.44जी.ए.1455 एवं खंडा की ट्रैक्टर ट्रॉली आर.जे. 09 आर.ई.4690 शामिल है।विभाग द्वारा म.प्र.खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

लोकसभा में सांसद सुधीर गुप्ता का सवाल

वस्त्र उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर

मंदसौर। मंदसौर-नीमच संसदीय क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में वस्त्र क्षेत्र से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी। सांसद सुधीर गुप्ता ने प्रश्न संख्या 550 के माध्यम से सरकार से पूछा कि हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन के उद्देश्य, चर्चा के प्रमुख बिंदु और इसके परिणाम क्या रहे।

सांसद ने अपने प्रश्न में यह भी जानना चाहा कि सम्मेलन के दौरान वस्त्र उद्योग के विकास, निवेश, निर्यात, पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस निर्णय लिए गए तथा केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए कौन से कदम प्रस्तावित किए गए हैं।

इस पर उत्तर देते हुए केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने बताया कि 8-9 जनवरी 2026 को गुवाहाटी (असम) में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय "एंड-टू-एंड सस्टेनेबिलिटीः विजन, ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन" रहा।

मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में अवसंरचना विकास, निवेश और विनिर्माण, निर्यात बढ़ाने, भारत के वस्त्रों की ब्रांडिंग, तकनीकी वस्त्र, नए फाइबर, कच्चे माल की उपलब्धता तथा पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई।

सरकार ने सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के तहत केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने, वर्ष 2030 तक वस्त्र निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करने, कारीगरों और बुनकरों की आय एवं बाजार पहुंच सुनिश्चित करने तथा वस्त्र मूल्य श्रृंखला में सस्टेनेबिलिटी और नवाचार को एकीकृत करने की दिशा में काम करने का संकल्प लिया। सांसद सुधीर गुप्ता के इस सवाल को वस्त्र उद्योग से जुड़े राज्यों और कारीगरों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे भारत को वैश्विक वस्त्र हब बनाने की दिशा में ठोस पहल को बल मिला है।

बजट से आम आदमी निराश, किसान मध्यम वर्ग के साथ छलः बाहेती

नीमच की उपेक्षा पर जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय हो : बाहेती

नीमच (निप्र)। जिला कांग्रेस अध्यक्ष तरुण बाहेती ने केंद्र सरकार के बजट 2026 को आम आदमी, किसान और मध्यम वर्ग विरोधी करार देते हुए उस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौर में जनता को राहत की उम्मीद थी, लेकिन यह बजट उम्मीदों पर पानी फेरने वाला साबित हुआ है। यह बजट आंकड़ों की बाजीगरी से भरा हुआ है, जबकि जमीन पर आम लोगों की मुश्किलें जस की तस बनी हुई हैं।

महंगाई से त्रस्त मध्यम वर्ग – उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर टैक्स में कोई राहत न देकर सरकार ने महंगाई को खुली छूट दे दी है। मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। हालात यह हैं कि मध्यम वर्ग की बचत खत्म हो रही है और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है।

किसानों की अनदेखी, फसलों के दाम बेहाल

बाहेती ने कहा कि नीमच जैसे कृषि प्रधान जिले के किसानों के लिए बजट पूरी तरह निराशाजनक है। सोयाबीन, लहसुन जैसी फसलों के दाम लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। किसानों को MSP की कानूनी गारंटी की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। खाद, बीज और कीटनाशकों की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। अफीम किसानों के लिए भी बजट में कोई ठोस राहत नहीं दी गई।

तरुण बाहेती ने कहा कि यदि बजट में नीमच के विकास, नई रेल सुविधाओं, अफीम किसानों की समस्याओं और औषधि व्यापार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो यह जिले के सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की विफलता है। यदि बजट के बाद भी नीमच की झोली खाली रही, तो जनप्रतिनिधियों को जनता को जवाब देना होगा।

बजट के बाद बाजार गिरा, भरोसा टूटा – बाहेती ने कहा कि बजट के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट सरकार की आर्थिक नीतियों पर अविश्वास को दर्शाती है। सरकार केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि छोटे व्यापारी और MSME आज भी मंदी से जूझ रहे हैं।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ – उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को लेकर बजट में कोई ठोस योजना नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य बजट में कटौती सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाती है। यह बजट 'सबका साथ' नहीं, बल्कि 'सबका विनाश' का दस्तावेज है।

प्रदेश में 'हर घर दस्तक' देकर खोजी जाएंगी दुर्लभ पांडुलिपियां, शुरू हुआ ज्ञान भारतम् मिशन

भोपाल। प्राचीन ज्ञान परंपरा और बौद्धिक संपदा को सहेजने के लिए प्रदेश में ज्ञान भारतम् मिशन के तहत एक बड़ा अभियान शुरू गया है। इसके तहत जीर्ण-शीर्ण पांडुलिपियों का वैज्ञानिक संरक्षण और डिजिटलीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने यह मिशन पिछले साल शुरू किया था। प्रदेश में संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। प्रदेश में जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है, जिसमे हर घर दस्तक अभियान चलाकर निजी संग्रहों और मठ-मंदिरों में छिपी पांडुलिपियों की पहचान की जानी है।

इस कार्य में छह से आठ महीने लगने का अनुमान है। पांडुलिपियां मिल जाने के बाद उनको संरक्षित करने का काम शुरू होगा। इस काम के लिए कर्मियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) का उपयोग करना सिखाया जाएगा। अधिकतर पांडुलिपियां हिंदी-संस्कृत के अतिरिक्त अन्य विलुप्त या कम प्रचलित भाषा में हो सकती हैं, इसलिए उनका भी प्रशिक्षण दिया गया है। पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय के उप संचालक नीलेश लोखंडे का कहना है कि भारतीय ज्ञान की यह परंपरा केवल हवाओं में नहीं, बल्कि उन लाखों पांडुलिपियों में दर्ज है जो आज हमारे मंदिरों, मठों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहों में धूल फांक रही हैं। इनका उपयोग व्यक्ति, समाज और देश हित में किया जा सकता है। यह बड़ी परियोजना है इसलिए इसमें सागर स्थित सेंटर आफ एक्सीलेंस डॉ. हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी मदद ली जा रही है।

आप भी कर सकते हैं योगदान – यदि किसी के घर में पूर्वजों द्वारा लिखी गई या संभालकर रखी गई कोई पांडुलिपि है तो संरक्षण के अभाव में वह नष्ट हो सकती है। इस मिशन के तहत उसे बचाया जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने स्वामित्व की पांडुलिपि सरकार दे सकता है, जिसका संरक्षण और डिजिटलीकरण कर उसे मूल संरक्षित प्रति वापस कर दी जाएगी। देश भर में 50 लाख पांडुलिपियों का अनुमानएक अनुमान के अनुसार, देश में 50 लाख से अधिक पांडुलिपियां हैं। इनमें दर्शन, आयुर्वेद, गणित, खगोल विज्ञान, साहित्य और वास्तुकला जैसे विषयों का अथाह भंडार है।

रेल यात्री सावधान ! बिना ओरिजिनल आईडी यात्रा की तो लगेगा भारी जुर्माना

भोपाल 9 फरवरी (एजेंसी)। रेलवे बोर्ड ने आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जारी निर्देशों के अनुसार, आरक्षित टिकट पर यात्रा के दौरान यात्रियों के समूह में से कम से कम एक यात्री को वैध पहचान पत्र मूल रूप में दिखाना होगा। यदि जांच के समय पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो संबंधित सभी यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और उनके विरुद्ध रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। रेलवे का कहना है कि यह व्यवस्था यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करने और फर्जी टिकट व अवैध यात्रा पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

कोटा और रियायत के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जरूरी – मान्य पहचान पत्र रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों ने किसी विशेष कोटे के अंतर्गत टिकट बुक कराया है या जिन्हें किराए में किसी प्रकार की रियायत प्रदान की गई है जैसे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, छात्र या अन्य आरक्षित श्रेणियां, उन्हें अपनी पात्रता से संबंधित वैध प्रमाण पत्र यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। जांच के दौरान प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में संबंधित रियायत अथवा आरक्षण सुविधा अमान्य मानी जाएगी और यात्री से नियमानुसार पूरा किराया व जुर्माना वसूला जा सकता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से रियायतों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। रेल यात्रा के दौरान टिकट और पहचान पत्र की जांच की जिम्मेदारी टीटीई और चेकिंग स्टाफ की होगी। जांच के समय टिकट पर दर्ज नाम का पहचान पत्र से मिलान किया जाएगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और किसी भी सरकारी विभाग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र पहचान सत्यापन के लिए मान्य होंगे।

जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक 12 को

नीमच,निप्र। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में 12 फरवरी 2026 गुरुवार को प्रातः: 10.30 बजे से जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही हैं। अपर कलेक्टर बी.एस.कलेश ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्धारित एजेंडा अनुसार जानकारी के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे

जयपुर 9 फरवरी (एजेंसी)। राजस्थान के सभी 31 वृद्धाश्रमों (ओल्ड एज होम) की जांच होगी। वहां रहने वाले बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं की हकीकत सामने आएगी। बुजुर्गों को मेडिकल की सुविधा मिल रही है कि नहीं, खाने की क्वालिटी, बिल्डिंग की स्थिति, साफ-सफाई से लेकर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, इन सब बिंदुओं पर हाईकोर्ट ने 15 फरवरी तक रिपोर्ट तलब की है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने यह जिम्मेदारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को दी है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। इसके लिए हमारा सिस्टम तैयार नहीं है।

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक ऐश्वर्य शर्मा के लिए माँ भगवती प्रिन्टर्स बंगला नं. 23, आईडीबीआई बैंक के सामने, नीमच, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश से मुदित एवं प्रकाशित। सम्पर्कः 9407423966। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र नीमच होगा।